

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम निदेशालय उत्तराखण्ड,
प्रेमनगर-देहरादून।

रेशम एवं रेशम अनुभाग:-1

देहरादून: दिनांक 06 नवम्बर, 2007

विषय:-वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-29 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना 0707-चाकी भवनों का निर्माण एवं रिनोवेशन के अन्तर्गत अवशेष रही धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-3108/रेशम/तक0अनु0/बजट/2007-08 दिनांक 29/10/2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में शासनादेश संख्या-422/XVI/07/7(42)/2007, दिनांक-30 मई, 2007 द्वारा राज्य सैक्टर की योजना 0707-चाकी भवनों का निर्माण एवं रिनोवेशन हेतु लेखानुदान के माध्यम से अवमुक्त धनराशि रु0-30,00,000.00 (रुपये तीस लाख मात्र) के अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष की अवशेष अवधि में राज्य सैक्टर की उक्त योजना पर व्यय के लिए अवशेष रही कुल रु0-51,50,000.00 (रुपये इक्यावन लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 1- इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यों के लिये ही किया जायेगा।
- 2- उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-599/XXVII (1)/2007, दिनांक-12 जुलाई, 2007 (छाया प्रति संलग्न) में दिये गये दिशा-निर्देशों तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- 3- किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रक्रिया (स्टोर्स पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्ठादन नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 आय व्यय सम्बन्धी नियम शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 4- अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।
- 5- निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक के आगणन/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ आगणनों पर सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय।
- 6- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

- 7- व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।
- 8- व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0-13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा, साथ ही यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत ही व्यय कर ली जायेगी।
- 9- लघु निर्माण कार्य व अन्य निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग की वर्तमान प्रचलित दरों पर ही आगणन गठित करके कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 10- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में अनुदान संख्या-29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-119-बागवानी और सब्जियों की फसलें-07-शहतूत की खेती एवं रेशम विकास 0707-चाकी भवनों का निर्माण एवं रिनोवेशन के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
- 11- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-368 (P)/XXVII/2007, दिनांक-28 नवम्बर, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
- संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

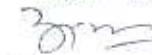
(उत्पल कुमार सिंह)
सचिव।

संख्या-^{934-A}/XVI/07/7(42) 2007 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
- 2- वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 5- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
- 6- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 8- गार्ड फाईल

आज्ञा से,



(अहमद अली)

अनु सचिव।